नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 245
दि. 08.06.2026,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सीमा विवाद पर संवाद का संकेत, भारत-नेपाल रिश्तों को नई मजबूती देने की कोशिश

काठमांडू और नई दिल्ली के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा संबंधी मतभेदों को लेकर नेपाल ने एक बार फिर सकारात्मक और संतुलित रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि वह सभी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से चाहता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के हालिया बयान को दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें टकराव की बजाय सहयोग, संवाद और साझा विकास की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया के कई देशों के बीच भू-राजनीतिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, नेपाल का यह संदेश क्षेत्रीय स्थिरता और पड़ोसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली की यात्रा पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच मौजूद किसी भी प्रकार की समस्या ऐसी नहीं है जिसे खुली बातचीत और आपसी विश्वास के माध्यम से सुलझाया न जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल की वर्तमान सरकार भारत को केवल एक पड़ोसी देश के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे साझेदार के रूप में देखती है जिसके साथ उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध सदियों पुराने हैं। उनके अनुसार दोनों देशों के रिश्ते केवल कूटनीतिक दायरे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और साझा विरासत से जुड़े हुए हैं।

विदेश मंत्री खनाल ने भारत-नेपाल संबंधों की विशेषता बताते हुए कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच जिस प्रकार का आत्मीय जुड़ाव है, वह दुनिया के बहुत कम देशों के बीच देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नागरिक न केवल एक-दूसरे के यहां आसानी से आते-जाते हैं, बल्कि पारिवारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर भी गहरे संबंध साझा करते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल केवल नक्शे पर पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि एक ही सभ्यता और सांस्कृतिक धारा के अभिन्न अंग हैं।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच समय-समय पर मतभेद सामने आते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने इन मुद्दों पर संयम बनाए रखा है और संवाद की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। नेपाल के विदेश मंत्री ने भी संकेत दिया कि सीमा विवाद जैसे संवेदनशील विषयों का समाधान केवल वार्ता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर ही संभव है।

नई दिल्ली प्रवास के दौरान शिशिर खनाल ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से विस्तृत बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, सीमा पार संपर्क, जल संसाधन प्रबंधन, पर्यटन और डिजिटल

कनेक्टिविटी जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों देशों को अपने आर्थिक सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।

भारत और नेपाल के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का उल्लेख करते हुए खनाल ने कहा कि नेपाल की आर्थिक प्रगति में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग के नए अवसर सामने आ रहे हैं। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात और सीमा पार ऊर्जा परियोजनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दी है। उनका मानना है कि आने वाले वर्षों में ऊर्जा सहयोग दोनों देशों के संबंधों का सबसे मजबूत आधार बन सकता है।

डिजिटल तकनीक और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को भी उन्होंने भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री ने जानकारी दी कि नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड (NCHL) और भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच हुए समझौते से दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान व्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस पहल से न केवल व्यापारिक गतिविधियां आसान होंगी, बल्कि पर्यटन और सीमा पार छोटे लेनदेन भी अधिक सुविधाजनक बन सकेंगे। यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली का विस्तार दोनों देशों के नागरिकों के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है।

नेपाल ने भारत द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं में दिए जा रहे सहयोग की भी सराहना की। शिशिर खनाल ने कहा कि वर्ष 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने जिस तत्परता से नेपाल की सहायता की, उसे वहां की जनता आज भी याद करती है। उन्होंने बताया कि भारत की सहायता से निर्मित अनेक स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण परियोजनाएं अब सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और उनका लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है।

नेपाल के विदेश मंत्री ने विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की मदद का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सहयोग से निर्मित अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र नेपाल के दूरदराज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्निर्माण में भी भारत का योगदान सराहनीय रहा है। उनका मानना है कि इस प्रकार की परियोजनाएं केवल विकास कार्य नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और मित्रता को भी मजबूत करती हैं।

तकनीकी और शैक्षणिक सहयोग को लेकर भी दोनों देशों के बीच नई पहलें सामने आ रही हैं। काठमांडू यूनिवर्सिटी और डिजिटल इंडिया मिशन के बीच हुए समझौतों का उल्लेख करते हुए खनाल ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में सहयोग भविष्य की जरूरत है। नेपाल तकनीकी विकास और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भारत के अनुभवों से लाभ उठाना चाहता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की ओर से आया यह सकारात्मक संदेश दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। हाल के वर्षों में कई अवसरों पर सीमा संबंधी विवादों और राजनीतिक बयानबाजी के कारण रिश्तों में तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन अब दोनों पक्ष विकास, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते दिखाई दे रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नेपाल का यह रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण एशिया में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत और नेपाल दोनों स्थिर एवं मजबूत संबंधों की आवश्यकता को समझते हैं। चीन सहित अन्य वैश्विक शक्तियों की बढ़ती सक्रियता के बीच नेपाल संतुलित विदेश नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है, जबकि भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नई मजबूती देने पर जोर दे रहा है।

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का बयान इस बात का संकेत देता है कि दोनों देश अपने मतभेदों को टकराव की बजाय संवाद के माध्यम से सुलझाने के पक्षधर हैं। साझा इतिहास, सांस्कृतिक निकटता, आर्थिक हित और लोगों के बीच गहरे रिश्ते भारत और नेपाल को एक-दूसरे का स्वाभाविक साझेदार बनाते हैं। ऐसे में यदि सीमा विवाद समेत अन्य लंबित मुद्दों पर लगातार बातचीत जारी रहती है तो दोनों देशों के संबंध आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत हो सकते हैं। यही कारण है कि काठमांडू से आया यह संदेश केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में सहयोग और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

युद्धविराम की दीवार पर फिर बारूद की चोट, बेरूत पर इजरायली हमले से मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव

तेल अवीव/बेरूत। मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी अस्थिरता के बीच एक बार फिर हालात गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम के कुछ ही समय बाद लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र को नई चिंता में डाल दिया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांड एवं संचालन केंद्रों को निशाना बनाया, जबकि लेबनान की ओर से इसे संप्रभुता का उल्लंघन और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई माना जा रहा है। इस घटनाक्रम ने युद्धविराम की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आशंका जताई जा रही है कि यदि दोनों पक्षों के बीच तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो क्षेत्र एक बार फिर व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। रविवार को हुए इन हमलों का केंद्र बेरूत का दहियेह इलाका रहा, जिसे हिजबुल्लाह का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमले के दौरान कई तेज धमाके सुनाई दिए और आसमान में धुएं के बड़े गुबार दिखाई दिए। कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि नुकसान और संभावित हताहतों को लेकर आधिकारिक आंकड़े तत्काल जारी नहीं किए गए। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का आकलन करने में जुटी हुई हैं।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई को इजरायल ने जवाबी हमला बताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उत्तरी इजरायल की दिशा में हुई कथित गोलीबारी और सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर यह सैन्य कार्रवाई आवश्यक थी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियां उनके नागरिकों और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बनी हुई हैं तथा किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा।

दूसरी ओर, लेबनान में इस हमले को लेकर चिंता और आक्रोश दोनों दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजधानी के दक्षिणी हिस्से को निशाना बनाया जाना केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। दहियेह क्षेत्र लंबे समय से हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता रहा है और यहां की किसी भी सैन्य गतिविधि का व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल में हुए युद्धविराम समझौते के बाद दोनों पक्षों के बीच अपेक्षाकृत शांति बनी हुई थी, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने उस संतुलन को कमजोर कर दिया है। पिछले कुछ सप्ताहों में सीमा क्षेत्रों में छिटपुट तनाव और आरोप-प्रत्यारोप की घटनाएं सामने आती रही थीं, किंतु राजधानी बेरूत तक सैन्य कार्रवाई पहुंचना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी देशों ने पहले भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी। कूटनीतिक हलकों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो संघर्ष केवल इजरायल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर असर डाल सकता है।

मध्य पूर्व पहले से ही कई भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में बेरूत पर हुआ यह हमला न केवल इजरायल-लेबनान संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र के लिए एक नई अस्थिरता का संकेत भी बन सकता है।

महंगाई को लेकर भाजपा पर अखिलेश का हमला, बोले- जनता की जेब पर लगातार बढ़ रहा बोझ

लखनऊ। बढ़ती महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई बेकाबू हो चुकी है और इसका सबसे अधिक असर गरीबों, मध्यम वर्ग तथा आम परिवारों पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है, जबकि जनता रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।

अखिलेश यादव ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे गृहस्थी का बजट पूरी तरह प्रभावित हो गया है। उनके अनुसार, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का सीधा असर हर घर पर पड़ता है, क्योंकि

इससे परिवहन लागत बढ़ती है और उसके साथ ही खाद्य पदार्थों से लेकर दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि आज आम आदमी पहले से कहीं अधिक आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। एक ओर महंगाई लगातार बढ़ रही है तो दूसरी ओर लोगों की आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही। उन्होंने कहा कि नौकरीपेशा वर्ग, छोटे व्यापारी, किसान और मजदूर सभी बढ़ती कीमतों के कारण परेशान हैं। घरेलू खर्चों का संतुलन बिगड़ रहा है और परिवारों के लिए बचत करना मुश्किल होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले महंगाई कम करने और लोगों को राहत देने के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जनता को उम्मीद थी कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करेगी, लेकिन वर्षों बाद भी लोगों को राहत नहीं मिली है। उनके अनुसार, बढ़ती कीमतों ने आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया है और सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाती नजर नहीं आ रही। उन्होंने बिजली दरों और स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उनका कहना है कि बढ़ते बिजली बिल और अन्य शुल्कों के कारण आम उपभोक्ता परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जब रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और बिजली जैसी मूलभूत सेवाएं महंगी होती हैं तो उसका व्यापक प्रभाव पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है और अंततः इसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। किसानों की स्थिति का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि कृषि क्षेत्र भी बढ़ती लागत से प्रभावित हो रहा है। डीजल, उर्वरक, बीज और अन्य कृषि संसाधनों की कीमतों में वृद्धि के कारण खेती करना महंगा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि उन्हें अपनी उपज का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को भी महंगाई से जोड़ते हुए कहा कि जब रोजगार के अवसर सीमित हों और आय के स्रोत न बढ़ रहे हों, तब महंगाई का असर और अधिक गंभीर हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट बना हुआ है और व्यापारिक गतिविधियां भी अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रही हैं। ऐसे में बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंताओं को और गहरा कर दिया है।

उन्होंने कहा कि महंगाई केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करती है। परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च करने में कठिनाई हो रही है। मध्यम वर्ग, जो पहले से ही आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, आज सबसे अधिक दबाव महसूस कर रहा है।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उनका कहना है कि नीतियों का केंद्रबिंदु जनता की राहत होना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में लोगों को राहत के बजाय लगातार बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महंगाई का मुद्दा आने वाले समय में भी विपक्ष और सरकार के बीच प्रमुख राजनीतिक बहस का विषय बना रहेगा। बढ़ती कीमतों, रोजगार, कृषि लागत और उपभोक्ता खर्च जैसे मुद्दे सीधे तौर पर जनता के दैनिक जीवन से जुड़े हैं, इसलिए इन पर राजनीतिक दलों की सक्रियता लगातार बनी रहने की संभावना है।

ईरान पर दबाव की नीति बरकरार, समझौते से पहले कोई राहत नहीं; ट्रंप ने दिए सख्त संकेत

न्यू जर्सी। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित कूटनीतिक समझौते को लेकर चल रही अटकलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वॉशिंगटन अपनी 'अधिकतम दबाव' की नीति से पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि जब तक कोई व्यापक और औपचारिक शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी और न ही अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को मुक्त किया जाएगा। उनके इस बयान को मध्य पूर्व की जटिल परिस्थितियों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एनबीसी न्यूज के चर्चित कार्यक्रम 'मीट द प्रेस' को दिए गए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी भी प्रकार की रियायत देने से पहले ठोस परिणाम देखना चाहता है। उनके अनुसार, केवल बातचीत या प्रारंभिक सहमति के आधार पर प्रतिबंधों में राहत देना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यदि ईरान सकारात्मक रवैया अपनाता

है, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सहयोग करता है और समझौते की सभी शर्तों का पालन करता है, तभी आर्थिक प्रतिबंधों को कम करने तथा फ्रीज की गई संपत्तियों के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।

ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका की प्राथमिकता केवल अस्थायी समझौता नहीं, बल्कि ऐसा स्थायी समाधान है जो क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों से यह स्पष्ट हो चुका है कि जल्दबाजी में किए गए समझौते अक्सर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते, इसलिए इस बार अमेरिका बेहद सतर्क दृष्टिकोण अपना रहा है।

राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी संभावित अंतरिम समझौते के लिए लेबनान को शामिल करना अमेरिका की अनिवार्य शर्त नहीं है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि मध्य पूर्व की स्थिति को समग्र रूप से देखते हुए अमेरिका क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है। विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान संकेत देता है कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ सीधे जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों को बाद के चरण में संबोधित कर सकता है।

साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कूटनीति और सैन्य शक्ति के बीच संतुलन बनाने की अपनी रणनीति को भी दोहराया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है और कुछ मुद्दों पर सकारात्मक प्रगति भी हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है या ईरान समझौते की दिशा में अपेक्षित सहयोग नहीं करता, तो अमेरिका कठोर कदम उठाने से नहीं हिचकेगा।

ट्रंप ने कहा कि कूटनीतिक प्रयास अमेरिकी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सैन्य विकल्पों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। उनके अनुसार, अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक विकल्प खुले रखे हुए है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमेरिका की सैन्य क्षमता सबसे मजबूत है और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने में संकोच नहीं किया जाएगा।

मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को लेकर भी ट्रंप ने अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सैनिकों की वापसी का कोई तत्काल कार्यक्रम नहीं है। उनके अनुसार, क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बलों की भूमिका अभी समाप्त नहीं हुई है और जब तक निर्धारित रणनीतिक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते, तब तक उनकी मौजूदगी बनी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैनिक केवल सैन्य उपस्थिति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता और दक्षता साबित की है। राष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिका के पास न केवल सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावी आक्रामक कार्रवाई करने की क्षमता भी मौजूद है। इस बयान को अमेरिका की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें कूटनीति के साथ शक्ति प्रदर्शन को भी रणनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को लेकर पूछे गए प्रश्न पर ट्रंप ने दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उपलब्ध संकेतों के आधार पर मोजतबा खामेनेई अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक व्यावहारिक और तर्कसंगत दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी सीमित है और भविष्य की नीतियों का आकलन समय के साथ ही संभव होगा। ट्रंप ने दावा किया कि हालिया संघर्षों के दौरान घायल होने के बाद खामेनेई सार्वजनिक रूप से अधिक सक्रिय नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि उन्होंने उनके वर्तमान ठिकाने या स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कोई ठोस जानकारी देने से इनकार कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के नेतृत्व में संभावित बदलावों का असर भविष्य की वार्ताओं पर पड़ सकता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर तेहरान के सत्ता केंद्र पर बनी हुई है।

संपादकीय

घुसपैठ और जनसांख्यिकीय असंतुलन : राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष बढ़ती चुनौती

भारत सरकार द्वारा देश में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारणों और उसके दूरगामी प्रभावों के अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन एक महत्वपूर्ण और समयोचित कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित इस समिति का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में आए असामान्य परिवर्तनों की जांच करना तथा उनके कारणों, प्रभावों और समाधान के संबंध में सरकार को सुझाव देना है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर की अध्यक्षता में गठित यह समिति विशेष रूप से अवैध घुसपैठ, अनियमित आवागमन तथा प्रशासनिक कमजोरियों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करेगी। जनसांख्यिकी किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का आधार होती है। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या संरचना स्वाभाविक कारणों के बजाय अवैध गतिविधियों या बाहरी हस्तक्षेपों के कारण तेजी से बदलने लगती है, तब उसके दूरगामी परिणाम सामने आते हैं। सीमावर्ती राज्यों, औद्योगिक नगरों और संवेदनशील क्षेत्रों में इस प्रकार के परिवर्तन प्रशासनिक चुनौतियों के साथ-साथ सामाजिक तनाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी जन्म दे सकते हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार इस विषय को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने संकेत दिया था कि कुछ क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों, रोजगार और सामाजिक समरसता पर दबाव बढ़ रहा है। इसी चिंता को आधार बनाकर अब सरकार ने संस्थागत स्तर पर अध्ययन और नीति निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है।

भारत में अवैध घुसपैठ का प्रश्न नया नहीं है। विशेष रूप से पूर्वी सीमा से जुड़े राज्यों में यह विषय कई दशकों से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा रहा है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद यह उम्मीद की गई थी कि वहां राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे लोगों का पलायन रुकेगा। लेकिन आर्थिक विषमताओं, रोजगार की कमी और अन्य परिस्थितियों के कारण बड़ी संख्या में लोग सीमाएं पार कर भारत आते रहे। समय के साथ यह प्रवृत्ति कई राज्यों तक फैल गई। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अध्ययनों में समय-समय पर इस विषय पर चिंता व्यक्त की जाती रही है। असम के पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने भी अपने कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे को गंभीर राष्ट्रीय चुनौती बताया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि अवैध घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय संरचना में व्यापक परिवर्तन हो सकता है। बाद में विभिन्न समितियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने भी इस विषय को राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ माना।

वर्ष 2000 में प्रस्तुत माधव गोडबोले समिति की रिपोर्ट ने भी अवैध प्रवासन के संभावित प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया था। रिपोर्ट में सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने, पहचान प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने तथा अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए ठोस तंत्र विकसित करने की आवश्यकता बताई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अलग-अलग मामलों की सुनवाई के दौरान इस विषय पर चिंता जताई और सरकारों को प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी। आज स्थिति यह है कि अवैध घुसपैठ का मुद्दा केवल सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं माना जाता। रोजगार, बेहतर जीवन और आर्थिक अवसरों की तलाश में आने वाले लोगों की उपस्थिति देश के अनेक हिस्सों में देखी जाती है। इससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, शहरी अवसंरचना प्रभावित होती है और कई बार प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। साथ ही नागरिकता, पहचान और मतदाता सूची से जुड़े प्रश्न भी समय-समय पर विवाद का कारण बनते हैं।

हालांकि इस विषय पर चर्चा करते समय संतुलन और संवेदनशीलता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। भारत एक लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित राष्ट्र है। इसलिए किसी भी कार्रवाई का आधार केवल कानून और प्रमाण होने चाहिए। किसी समुदाय, धर्म या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह के बजाय तथ्यात्मक जांच और संवैधानिक प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही दृष्टिकोण राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द के लिए भी आवश्यक है।

कैमरे की बींधती निगाहों से तंग विराट कोहली

> विराट कोहली,क्रिकेट खेल की श्रेष्ठता और अधिकतम जश्न मनाने का प्रतीक, लगता है अब कैमरों की निरंतर बींधती आंख से तंग आ चुका है। आह, काश उन्हें एक पल के लिए भी उनकी लगातार पीछा करती नजरों से छुटकारा मिल...

विराट कोहली,क्रिकेट खेल की श्रेष्ठता और अधिकतम जश्न मनाने का प्रतीक, लगता है अब कैमरों की निरंतर बींधती आंख से तंग आ चुका है। आह, काश उन्हें एक पल के लिए भी उनकी लगातार पीछा करती नज़रों से छुटकारा मिल पाता- नज़रें जो उनकी निजी ज़िंदगी तक में ताका-झांकी और दखलअंदाज़ी करती है, यहां तक कि उनके प्रशिक्षण सत्रों तक में पीछा नहीं छोड़तीं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में, जिसमें उनकी संवेदनशील सोच और बेहतरीन वाक्पटुता सामने आई, कोहली ने कैमरों की उन पर लगातार घूमती नज़र से एक विनम्र अपील की : 'मेहरबानी कर मुझे अकेला छोड़ दो'।

वह खिलाड़ी जो उस युग का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसमें जीत मनाना वह उन्माद है जो आक्रामक, भयभीत करने वाली शारीरिक भंगिमा के जरिए पाया गया हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उनके अंतस को इतना परेशान कर डाला कि उन्हें इस प्रकार शिकायत करनी पड़ी। जब किसी खिलाड़ी की निजता में कैमरों की दखल देने वाली नज़रें घुसपैठ करने लगें तो ऐसी नाराज़गी होना जायज है।

जिस दौर में हम जी रहे होते हैं, उससे आकार पाते हैं। क्रिकेट के इतिहास में, जिस प्रकार इसके कप्तान खुद को दुनिया के सामने पेश किया करते थे, तो उनके बदलते व्यवहार का मामूली सा अध्ययन भी बहुत कुछ बता सकता है। आखिरकार, हम वही बनते हैं जो कुछ हमारे अंदर भरा जाता है। इतिहास के इस पहलू की ऐसी पड़ताल जाहिर तौर पर शौकिया है, जिसकी प्रेरणा अधिकांशतः कोहली की सच्ची अपील से मिली है।

सत्तर के दशक में, जब 'स्पिन के सरदार' बिशन सिंह बेदी भारत की कप्तानी कर रहे थे, उस वक्त जीत मनाने का इज़हार केवल एक हल्की-सी मुस्कान और हल्की ताली बजाकर किया जाता। तब, हर जगह पीछा करने वाली कैमरों की प्रवृति अपनी शैशवास्था में थी, और लोग अपने हीरो को पहचानने के लिए ज़्यादातर छपी हुई तस्वीरों पर ही निर्भर थे। यहां तक कि सत्तर के दशक की यह सहज हल्की-सी मुस्कान भी बीते दशक के मंसूर अली खान पटौदी के भावशून्य व करीब अबूझ व्यक्तित्व से नाटकीय रूप में अलग थी।

सुनील गावस्कर द्वारा व्यावहारिक दूरी बनाए रखना, कपिल देव के ज़मीन से जुड़े उपदेश-भारतीय कप्तानों की लंबी कतार एक ऐसे दौर से जुड़ी थी जहां प्रदर्शनबाजी कम थी; यह कैमरों की दखलअंदाज़ी करती नज़रें धारदार होने से पहले का दौर था। आज के उलट, वह एक बदलाव का दौर था, जब जीत की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण और शांत तरीके से करना आम बात थी—जो आज के दौर में किसी पुरातन युग के अवशेष जैसा है।

सचिन तेंदुलकर ने संकोची और अंतर्मुखी मोहम्मद अज़हरुद्दीन से कप्तानी संभाली थी और जब तक सौरव गांगुली को सौंपी, तब तक सार्वजनिक नजरों का देखने का ढंग बदलने लगा था, जो धीरे-धीरे और ज़्यादा दखल देने वाली होती जा रही थीं। कम बोलने वाले तेंदुलकर ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई, जहां लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखने से उनके प्रति सम्मान और भी गहरा हो जाता था। वह क्रिकेट की दुनिया के बाहर अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम बातें बताते थे; एक बेहद निजी और एकांत पसंद व्यक्तित्व, जिसका कम बोलना उनके कद और लोकप्रियता को और भी बढ़ा देता। मीडिया से बात करने में उनकी हिचकिचाहट एक ऐसे इंसान की छवि दर्शाती थी जो उन लोगों के बीच सहज महसूस नहीं करता था जिन पर उसे भरोसा न हो, फिर भी वह उन्हें नाराज़ न करने का पूरा ध्यान रखते थे। बींधने वाले कैमरे उस समय देर से आए, तब तेंदुलकर के नाम का वज़न ही इतना ज़्यादा हो चुका था कि उसका बोझ सिर्फ़ वही उठा सकते थे। एक तरह से, उनके व्यक्तित्व का ओज़ आस-पास के माहौल को इतना शालीन कर देता था कि वह सबको उनकी निजता में दखल न देने की सावधानी बरतने के लिए 'मजबूर' कर दे।

मुखर स्वभाव वाले सौरव गांगुली को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी, और उन्हें अपनी निजी और सार्वजनिक ज़िंदगी के बीच की सीमाएं मिटाने में आनंद आता था। उन्होंने विवादों का सामना किया और यहां तक कि उन्हें बनाया भी, लेकिन खुद को उनसे ज़्यादा परेशान हुए बगैर। बदलते समय में, बाहरी शोर-शराबे से खुद को बचाने के लिए 'मोटी खाल' होना ज़रूरी हो गया, वह 'खूबी' जिसकी कमी शायद उनके उत्तराधिकारी राहुल द्रविड़ में थी। द्रविड़ तो खैर अपने शानदार रिकॉर्ड बनाने में ही पूरी तरह मग्न रहे। उनके लिए कप्तानी परेशानी का सबब थी, और इसके थकाऊ प्रबंधकीय पहलू से धीरे से दूर हट गए।

लगता है महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी सहजता से उस 'राक्षस' के खतरनाक इरादों को बूझ लिया था, जोकि कैमरा बनता जा रहा था। उन्होंने इसकी चुभती मौजूदगी को कुंद और बेअसर करने के लिए एक तरीका ईजाद कर लिया। बोलने का सधा हुआ और नपा-तुला अंदाज़—जो अक्सर चुप्पी धारण करने के करीब होता था—उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा बन गया। जो लोग किसी कहानी या विवाद की फिराक में रहते थे, मानो किसी जादू की तरह, खुद छिटक जाते। उनका कम बातूनी किंतु मिलनसार स्वभाव, जो शोर-शराबे वाले माहौल को भी चुप करवा दे, इसका बेहतरीन उदाहरण रहेगा कि बिना दुश्मन बनाए दूरी कैसे रखी जाती है।

ऊंची आवाज़, भावनात्मक उदगार और दबी नाराज़गी के खुलकर इज़हार के बाद जो कुछ आया वह कोहली की हताशा को परिभाषित करने वाला है—और आश्चर्यजनक रूप से उनके जश्न मनाने के अंदाज़ को भी—उसमें परिणति का अहसास होना बदा था। रोहित शर्मा एक ऐसी भूमिका में ढले, जिसको आकार व्यवहार के तौर-तरीकों के लंबे इतिहास से मिला,वह जिन्हें आधुनिक क्रिकेट न केवल बढ़ावा देता है बल्कि उनका सामान्यीकरण भी करता है। रोहित उस स्कूल मास्टर की तरह थे, जो ऊपर से सख्त होने का दिखावा करता है, लेकिन दिल से एक प्यारा इंसान होता है; अपने खिलाड़ियों को दीं उनकी झिड़कियां कभी भी बदनीयत नहीं लगीं।

अपने प्रदर्शन से पहचान बनाने की कोशिश करने और आखिरकार एक आदर्श एवं मशहूर हस्ती के तौर पर खुद को स्थापित करने के मुकाम तक—एक सफल खिलाड़ी कभी यह मंजिल एक तयशुदा लीक पर चलकर पाता था। लेकिन, आज के दौर में, ऐसा रास्ता बहुत सपाट, बेमज़ा लगता है। यह न तो किसी को रोमांचित करता है और न ही लोगों का ध्यान खींचता है। क्रिकेट का मैदान अपने आप में और भी विस्तृत हो गया है। निजता अब सार्वजनिक है और सार्वजनिकता निजता है। यह मुकाबला अब उत्तरोतर एक नाटक की तरह होता जा रहा है, जिसमें मुख्य कलाकारों को सिर्फ़ खेल के मैदान पर ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी 'रील-मेकर' बनकर अभिनय करना पड़ता है।

जब काफी संवेदनशील और अपनी बात को बेहतर ढंग से रखने वाले कोहली निजता और मीडिया की निरंतर दखल देती नजरों से बचने की ज़रूरत के बारे में बात करते हैं, तो शायद वे उस बड़ी सच्चाई के बारे में बात करना भूल गए, जिसे खुद आधुनिक खेलों के बाजारीकरण ने ही पैदा किया है। उसके लिए, वह एक ऐसी आकर्षक हस्ती हैं, जिनकी उपलब्धियां, नखरे और यहां तक कि गुस्से से भरे उनके अंदाज भी, एक चुंबक की तरह काम करते हैं, दर्शकों और कैमरों, दोनों को एक समान अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या हुआ अगर वे अब मीडिया की दखलअंदाजी से तंग आ गए हैं? नाटक और नाटकीयता के प्रति हमारी भूख इस कदर बढ़ गई है कि अगर कोहली न भी होते, तो हम उन जैसा गढ़ लेते।

आज के ज़माने के सितारे कैमरे के सहारे ही जीते हैं और उसी के हाथों खत्म भी हो जाते हैं। यह उनके लिए शोहरत पाने की खिड़की है-एक ऐसा ज़रिया, जो अंततः एक गिद्ध बनकर उन्हें ही निगल सकता है। -लेखक वरिष्ठ खेल संवाददाता हैं।

प्रेरणा

जब व्यवस्था ने कहा - 'अब भगवान ही मालिक है'

हमारे देश में एक पुरानी परंपरा रही है। जब कोई समस्या छोटी होती है तो अधिकारी उसे देखते हैं, जब बड़ी होती है तो मंत्री देखते हैं और जब बहुत बड़ी हो जाती है तो एक समिति बना दी जाती है। लेकिन अब नया भारत है। यहां समस्याओं के समाधान भी आधुनिक हो गए हैं। अब जब कोई समस्या नियंत्रण से बाहर होने लगती है तो उसे किसी और के खाते में डाल दिया जाता है। यह जिम्मेदारी हस्तांतरण का ऐसा शानदार मॉडल है कि प्रबंधन संस्थानों में इस पर शोध होना चाहिए।

पेपर लीक का मामला भी कुछ ऐसा ही है। कभी जमाना था जब प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचता था और छात्र उसे देखकर भविष्य तय करते थे। अब प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप ग्रुप और गुप्त चैनलों की यात्रा पूरी कर लेता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र से ज्यादा घूमने-फिरने का शौकीन हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि हर बार पेपर लीक होने पर वही पुराना दृश्य सामने आता है। छात्र परेशान, अभिभावक निराश, कोचिंग संस्थान सक्रिय, विपक्ष हमलावर और सरकार आश्वासन देती हुई दिखाई देती है। कुछ दिनों तक टीवी चैनलों पर बहस चलती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा उमड़ता है, फिर धीरे-धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद नई परीक्षा की घोषणा होती है और सब लोग फिर उम्मीदों की गठरी बांधकर लाइन में लग जाते हैं।

ऐसा लगता है कि पेपर लीक अब कोई अपराध नहीं बल्कि एक परंपरा बनता जा रहा है। जैसे हर साल मानसून आता है, त्योहार आते हैं, वैसे ही कुछ परीक्षाओं के साथ पेपर लीक की संभावना भी जुड़ गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि मानसून का मौसम विज्ञान विभाग अनुमान लगाता है और पेपर लीक का अनुमान छात्र लगाने लगे हैं।

सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति उन छात्रों की होती है जो वर्षों तक मेहनत करते हैं। सुबह चार बजे उठकर पढ़ना, कोचिंग के नोट्स रटना, ऑनलाइन टेस्ट देना, दोस्तों से दूरी बनाना और परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाना—यह सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी मेहनत को रबड़ से मिटा दिया हो। उनके लिए यह केवल परीक्षा नहीं होती, बल्कि जीवन के कई वर्षों का निवेश होता है। व्यवस्था की खूबी यह है कि वह हर बार एक नया कारण खोज लेती है। कभी किसी कर्मचारी की गलती, कभी किसी एजेंसी की चूक, कभी तकनीकी समस्या और कभी संगठित गिरोह। लेकिन यह प्रश्न शायद ही कभी पूछा जाता है कि यदि हर बार अलग-अलग कारण हैं तो परिणाम एक जैसा क्यों है? आखिर ऐसी कौन-सी जादुई शक्ति है जो हर परीक्षा को लीक होने की दिशा में धकेल देती है?

व्यंग्य की बात यह है कि हमारे यहां समस्याओं के समाधान से ज्यादा उनकी व्यवस्थाएं विकसित हो जाती हैं। सड़क पर गड्ढे हों तो लोग उन्हें पहचानना सीख जाते हैं। बिजली जाए तो इन्वर्टर खरीद लेते हैं। पानी कम आए तो टंकी लगवा लेते हैं। उसी तरह पेपर लीक की समस्या के बीच छात्रों ने भी मानसिक रूप से खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है कि परीक्षा हो भी सकती है और रद्द भी हो सकती है।

यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में लिखना पड़ सकता है—"हम केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कराते, बल्कि परीक्षा रद्द होने के बाद मानसिक संतुलन बनाए रखने की भी ट्रेनिंग देते हैं।" शायद इसके लिए अलग बैच भी शुरू हो जाएं।

कई बार लगता है कि देश में दो समानांतर व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक वह जो नियम पुस्तिका में लिखी हुई है और दूसरी वह जो व्यवहार में दिखाई देती है। नियम पुस्तिका कहती है कि परीक्षा निष्पक्ष होगी, गोपनीयता बनी रहेगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। व्यवहारिक दुनिया कहती है कि पहले देखिए परीक्षा होती भी है या नहीं।

युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास समय सीमित होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की आयु सीमा, आर्थिक परिस्थितियां और पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्हें लगातार दबाव में रखती हैं। ऐसे में बार-बार परीक्षा रद्द होना उनके आत्मविश्वास पर गंभीर प्रभाव डालता है। कई प्रतिभाशाली छात्र निराश होकर अपनी दिशा बदल लेते हैं। यह केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं बल्कि देश की प्रतिभा का नुकसान भी है। यदि किसी राष्ट्र को अपनी युवा शक्ति पर गर्व है तो उसे उनकी मेहनत की रक्षा भी करनी होगी। परीक्षा प्रणाली केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है; यह अवसर की समानता का आधार है। जब इस आधार पर ही सवाल उठने लगें तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

विडंबना यह है कि तकनीक के इस युग में जहां अंतरिक्ष मिशन सफल हो रहे हैं, डिजिटल भुगतान सेकंडों में हो रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता नई संभावनाएं खोल रही है, वहीं प्रश्नपत्र की सुरक्षा अब भी चुनौती बनी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि तकनीक कमजोर है, बल्कि यह कि इच्छाशक्ति, जवाबदेही और निगरानी में कहीं न कहीं कमी है।

समस्या का समाधान कठिन नहीं है, लेकिन उसके लिए गंभीरता चाहिए। परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करनी होगी, सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना होगा और दोषियों को ऐसी सजा देनी होगी जो दूसरों के लिए उदाहरण बने। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी से विश्वास वापस नहीं आता।

आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं को यह भरोसा दिलाया जाए कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि व्यवस्था उनके साथ खड़ी है, न कि केवल घटनाओं के बाद सफाई देने के लिए तैयार बैठी है।

वरना वह दिन दूर नहीं जब छात्र परीक्षा फॉर्म भरते समय पाठ्यक्रम, आयु सीमा और शुल्क के साथ एक और कॉलम खोजने लगेंगे—"पेपर लीक होने की संभावित तिथि।" और तब शायद व्यवस्था मुस्कुराकर कहेगी, "हमने तो पूरी कोशिश की थी, अब आगे ऊपरवाले की मर्जी।"

यही वह स्थिति होगी जब लोग कहेंगे कि समस्या पेपर लीक की नहीं रही, बल्कि उस सोच की हो गई है जिसमें विफलताओं को सामान्य मान लिया जाता है। किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं कि उसकी व्यवस्था हार मान ले और नागरिकों से कहे—"अब भगवान ही मालिक है।"

अवैध और अनियोजित निर्माण की बीमारी

देश की राजधानी में कुछ दिनों पहले अवैध रूप से बन रही एक इमारत गिरी, जिसमें छह लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद अवैध तरीके से बनाए और संचालित किए जा रहे एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। अपने देश में सरकारी तंत्र और अवैध निर्माण करने वालों की मिलीभगत से इस तरह की घटनाओं में जिस तरह जान-माल का नुकसान होता है, उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है।

यह सिलसिला पिछले कई दशकों से चला आ रहा है, पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। राजधानी सहित पूरे देश में नगर निकायों के नाकारापन से लोग अवैध तरीके से घर, होटल आदि बनाते रहते हैं। जब मानकों की अनदेखी करके अवैध-अनियोजित निर्माण होते हैं तो उनके गिरने के साथ-साथ अथवा उनमें सुरक्षा मानकों की अवहेलना के कारण आग लगने की घटनाएं होना स्वाभाविक है।

ज्यादातर मामलों में अवैध निर्माण कराने वाले अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी समझते नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं। अपने देश में नियम-कानूनों की जैसी अनदेखी होती है, वह शायद ही कहीं और देखने को मिलती हो। देश में नियम-कानूनों के साथ अनुशासन और जिम्मेदारी का परिचय देने से भी इन्कार किया जाता है। औसत लोग एक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं होते, वही स्थिति सरकारी तंत्र के लोगों की भी है। नगर निकायों और शहरीकरण की निगरानी एवं नियमन करने वाले अधिकारियों का हाल शायद सबसे बुरा है। वे तमाम लापरवाही और भ्रष्टाचार के बाद भी ऐसी सजा नहीं पाते, जो नजीर बन सके। नगर निकायों की लापरवाही के चलते अनियोजित निर्माण केवल शहरों के पुराने इलाकों के साथ उन ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं हो रहा है, जो समय के साथ शहरीकरण के दायरे में आ गए। अब तो यह विकास प्राधिकरणों की ओर से बसाए गए नए इलाकों में भी हो रहा है। कहीं लोग घरों को तोड़कर फ्लैट बना रहे हैं तो कहीं दुकानें और अन्य व्यासायिक भवन। ऐसे निर्माण में भवन निर्माण संबंधी मानकों के साथ सुरक्षा उपायों और खासकर आग से बचाव के उपायों की परवाह नहीं की जाती।

जब शहरों के पुराने या फिर ग्रामीण इलाकों में जर्जर भवनों में अतिरिक्त अवैध निर्माण होता है तो उनके गिरने का खतरा अधिक रहता है। आम तौर पर जब यह अवैध निर्माण हो रहा होता है तो उसे रोकने के लिए जिम्मेदार नगर निकायों के अधिकारी-कर्मचारी कोई कदम नहीं उठाते। ज्यादातर मामलों में वे पैसे लेकर अवैध निर्माण होने देते हैं। वे इसकी चिंता नहीं करते कि इससे क्षेत्र विशेष में आबादी का दबाव बढ़ेगा अथवा व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने से भीड़-भाड़ और प्रदूषण के साथ गंदगी बढ़ेगी तथा नागरिक सुविधाओं का अभाव बढ़ेगा।

कहने को तो शहरीकरण को लेकर हर तरह के नियम-कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका उल्लंघन ही अधिक होता है। इस उल्लंघन का एक बड़ा कारण नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य नेताओं की ओर से केवल अपने वोट बैंक को प्राथमिकता देना है। कई बार तो वे खुद ही अवैध निर्माण में सहयोग करते हैं और इसकी भी कोशिश करते हैं कि अवैध रूप से बसाई गईं बस्तियों का नियमितीकरण कर दिया जाए। सरकारें भी वोट बैंक के लोभ में ऐसा कर देती हैं। जब ऐसा होता है तो ऐसी बस्तियों में और अधिक अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण होने लगता है।

आज कोई भी राजनीतिक दल अवैध-अनियोजित निर्माण को रोकने के लिए गंभीर नहीं। इसी कारण शहरों की सूरत बिगड़ती जा रही है और उनमें नागरिक सुविधाओं का अभाव बढ़ रहा है। चूंकि रिहायशी अथवा व्यावसायिक इमारतों में अवैध निर्माण के बाद भी सरकारी एजेंसियां कोई ठोस कार्रवाई नहीं करतीं, इसलिए उनके गिरने या उनमें आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में ही पिछले कुछ माह में घरों, होटलों और कारखानों में आग लगने के कारण मरने और घायल होने वालों की संख्या बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार बीते पांच माह में दिल्ली में आग लगने की अलग-अलग घटनाओं में करीब 45 लोगों की जान गई है। अनेक घटनाओं में यह भी सामने आया कि कोई भवन गिरने या आग लगने पर बचाव कर्मियों को अतिक्रमण के चलते घटनास्थल पर पहुंचने में देरी हुई। इस देरी के चलते कई ऐसे लोगों की जान गई, जिन्हें बचाया जा सकता था। अवैध निर्माण की तरह से गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक में अतिक्रमण भी अपने देश की एक बड़ी समस्या है। पिछले कुछ समय से देशवासियों को यह सपना दिखाई जा रहा है कि अगले लगभग 25 वर्षों यानी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक मजबूती से नहीं बनता और न ही कुछ क्षेत्रों में विकसित राष्ट्रों के पैमानों के हिसाब से प्रगति करने से। भारत विकसित राष्ट्र तब बनेगा, जब सरकारी एजेंसियां और देश के नागरिक नियम-कानूनों का पालन करेंगे। दुर्भाग्य से अपने देश में हर काम के लिए शार्ट कट खोज लिए गए हैं। एक समस्या यह भी है कि देश में किसी भी तरीके का जो सार्वजनिक निर्माण हो रहा है, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती जा रही है। चूंकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इंजीनियरों और ठेकेदारों को गुणवत्तापरक काम करने की आदत ही नहीं रह गई। जब भी घटिया निर्माण या फिर सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण जान-माल की हानि होती है, तब मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा कर जांच बैठा दी जाती है।

अभियान

शनि और शिव की संयुक्त कृपा का दिन : जीवन के संकट दूर करने वाला पावन शनि प्रदोष व्रत

सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि, व्रत और पर्व का अपना विशेष महत्व है। इनमें कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जिन्हें अत्यंत दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत ऐसा ही एक दिव्य संयोग है, जब भगवान शिव और भगवान शनिदेव दोनों की आराधना का पुण्य एक साथ प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन व्यक्ति के जीवन में चल रही बाधाओं, कष्टों, आर्थिक समस्याओं और ग्रहजनित परेशानियों को दूर करने की अद्भुत क्षमता रखता है। वर्ष 2026 में 27 जून को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन कई सकारात्मक ज्योतिषीय संयोग भी बन रहे हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को सृष्टि के कल्याणकारी देवता के रूप में पूजा जाता है। वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी प्रार्थना भी सुनते हैं और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दूसरी ओर शनिदेव को कर्मों का न्याय करने वाला ग्रह माना गया है। शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुरूप फल प्रदान करते हैं। इसलिए जब शनिवार के दिन प्रदोष व्रत आता है, तब यह दिन भक्ति और कर्म दोनों के संतुलन का संदेश देता है।

धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि प्रदोष काल भगवान शिव का अत्यंत प्रिय समय होता है। मान्यता है कि इस समय देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को विशेष रूप से स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि प्रदोष व्रत का पालन करने वाले श्रद्धालु संध्या काल में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। यदि यही प्रदोष शनिवार को पड़े तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन शनिदेव की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त होती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, सफलता और स्थिरता प्रदान करती है। वहीं अशुभ स्थिति में जीवन में बाधाएं, देरी, आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि शनि की शांति के लिए लोग विभिन्न उपाय करते हैं और शनि प्रदोष व्रत को विशेष महत्व देते हैं।

वर्ष 2026 में शनि प्रदोष व्रत 27 जून को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 26 जून की रात्रि से प्रारंभ होकर 28 जून के आरंभिक समय तक रहेगी। प्रदोष काल की पूजा का श्रेष्ठ समय 27 जून की संध्या में रहेगा। इस दौरान भगवान शिव का अभिषेक, मंत्रजाप और शनिदेव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है।

इस व्रत की शुरुआत प्रातःकाल स्नान और शुद्धिकरण से होती है। भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद भगवान शिव और शनिदेव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन संयम, सात्विकता और ईश्वर चिंतन का पालन किया जाता है। कई श्रद्धालु फलाहार करते हैं जबकि कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ किया जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव का ध्यान किया जाता है। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के दौरान बेलपत्र, भांग, धतूरा और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करने से शनि दोषों में कमी आती है और जीवन के संकट दूर होते हैं।

पूजा के समय "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जप अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंत्र शिव भक्ति का मूल मंत्र है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी विशेष लाभकारी माना गया है। यह मंत्र स्वास्थ्य, दीर्घायु और भय से मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है।

शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। शनिदेव को काले तिल, काली उड़द और नीले या काले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। उनके मूल मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का 108 बार जाप करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों की कुंडली में साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि महादशा चल रही हो, उन्हें इस दिन विशेष रूप से मंत्रजाप करना चाहिए।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि प्रदोष व्रत केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन किए गए दान-पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान से ग्रहों की अशुभता कम होती है और पुण्य में वृद्धि होती है। इस दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं, काले वस्त्र और अन्न का दान करना शुभ माना गया है। जरूरतमंदों, गरीबों और श्रमिकों को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

पीपल वृक्ष की पूजा भी इस दिन विशेष फलदायी मानी गई है। शनिवार की संध्या में पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा से वृक्ष की परिक्रमा कर भगवान से जीवन की बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे शनि की पीड़ा कम होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं।

शनि प्रदोष व्रत का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में केवल भाग्य नहीं, बल्कि कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं, जबकि भगवान शिव उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए यह व्रत केवल ग्रह शांति का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मसुधार और आत्मचिंतन का अवसर भी है।

आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में लोग मानसिक अशांति, आर्थिक दबाव और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में शनि प्रदोष व्रत व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। पूजा, मंत्रजाप और ध्यान के माध्यम से मन को शांति मिलती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

व्यापारियों के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नौकरीपेशा लोगों को करियर में उन्नति और सम्मान प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। विद्यार्थी भी इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की आराधना कर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की कामना करते हैं।

ज्योतिषीय दृष्टि से वर्ष 2026 का यह शनि प्रदोष और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दिन शुभ योगों का प्रभाव साधना और पूजा के फल को बढ़ाने वाला माना गया है। ऐसे में जो लोग लंबे समय से किसी समस्या, बाधा या ग्रह दोष से परेशान हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर लेकर आ रहा है।

धर्मग्रंथों में कहा गया है कि भगवान शिव की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और शनिदेव की प्रसन्नता से कर्मों के मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। जब इन दोनों दिव्य शक्तियों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होने लगता है।

अतः 27 जून 2026 का शनि प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति, ग्रह शांति और जीवन सुधार का एक महत्वपूर्ण अवसर है। श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से की गई पूजा न केवल ईश्वर की कृपा दिलाती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का भी संचार करती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में शनि प्रदोष व्रत को अत्यंत पुण्यदायी, कल्याणकारी और जीवन परिवर्तनकारी व्रत माना गया है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

गुजरात स्थित विश्व की एकमात्र फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का वैश्विक डंका 96 देशों के प्रतिनिधि प्राप्त कर रहे हैं विभिन्न जांच एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के साथ एनएफएसयू का गौरवपूर्ण योगदान : अमेरिका तक पहुंचीं देश में निर्मित फोरेंसिक उत्पाद; 17 राज्यों में 300+ मोबाइल वैन सेवाएं दे रही हैं

▸▸ अनुसंधान द्वारा शिक्षा' के ध्येय के साथ एनएफएसयू ने स्थापित किए नए मापदंड : विमान दुर्घटना में डीएनए प्रोफाइलिंग से लेकर स्पोर्ट्स साइंस क्षेत्र में हासिल की विशिष्ट उपलब्धियां

▸▸ यूनिवर्सिटी के अब तक देश-विदेश में कुल 13 कैंपस संचालित

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2009 में गांधीनगर में स्थापित नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) ने मात्र 14 वर्षों की अल्प अवधि में अक्टूबर 2020 में 'इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस (आईएनआई)' का गौरवपूर्ण दर्जा प्राप्त किया है।

संस्थापक कुलपति एवं भारत के वरिष्ठतम फोरेंसिक वैज्ञानिक 'पद्मश्री' डॉ. जे.एम. व्यास के कुशल नेतृत्व में एनएफएसयू ने शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जांच के क्षेत्र में एक विशिष्ट शैक्षणिक मॉडल स्थापित किया है। वैश्विक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय कैंपस एनएफएसयू गुजरात और भारत की ऐसी एक विशिष्ट सरकारी यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करते हुए युगांडा के जिंजा में अपना विदेशी कैंपस स्थापित किया है। अब तक विश्व के 96 देशों के प्रतिनिधियों ने यहां से फोरेंसिक साइंस का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। संस्था की शैक्षणिक उत्कृष्टता और ग्रीन कैंपस से प्रभावित होकर विश्व के अनेक देशों ने अपने यहां एनएफएसयू का कैंपस स्थापित करने के लिए आधिकारिक प्रस्ताव भेजे हैं। निरंतर विस्तार कर रही इस यूनिवर्सिटी के मई 2026 तक देश-विदेश में कुल 13 परिसर हैं।

ग्राउंड लेवल जांच के लिए 300 से अधिक मोबाइल फोरेंसिक वैन

अपराधों की वैज्ञानिक जांच को तेज और सटीक बनाने तथा न्यायालय में प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से एनएफएसयू ने भारत में ही निर्मित अत्याधुनिक 'मोबाइल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन' विकसित की है। यह वैन 24×7 प्रशिक्षित विशेषज्ञों और विशेष फोरेंसिक किट्स के साथ सेवाएं प्रदान करती है। देश के 17 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसी 300 से अधिक मोबाइल वैन कार्यरत हैं, जो न्याय प्रक्रिया को गति देने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं।

स्टार्टअप क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' का सपना साकार

एनएफएसयू ने अनुसंधान और स्टार्टअप्स को वेग देने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 'फोरेंसिक इनोवेशन काउंसिल' तथा एसएसआईपी के सहयोग से 'फोरेंसिक इनोवेशन सेंटर' की स्थापना की है। यहां अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस केंद्र के माध्यम से विकसित फोरेंसिक जांच से संबंधित 20 से अधिक 'मेक इन इंडिया' उत्पाद आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर और यूरोप सहित कई देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संस्था ने भारत और अमेरिका दोनों में विशिष्ट पेटेंट स्वीकृतियां प्राप्त कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

डिजास्टर इन्वेस्टिगेशन और स्पोर्ट्स साइंस में मील का पत्थर साबित हुई उपलब्धियां

राष्ट्रीय आपदाओं और जटिल मामलों में भी एनएफएसयू अग्रणी रही है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट के निकट हुई दुखद एयर इंडिया फ्लाइट-171 विमान दुर्घटना में कुल 265 मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए एनएफएसयू की टीम ने अत्यंत तेज गति से डीएनए प्रोफाइलिंग का भगीरथ कार्य पूरा किया था। इसके अतिरिक्त; खेल जगत में खिलाड़ियों के पोषण परीक्षण और प्रतिबंधित पदार्थों की पहचान के लिए यहां 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर न्यूट्रिशनल टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्सपर्सन' (CoE-NSTS) की स्थापना की गई है, जो देश में अपनी तरह का एक अनूठा वैज्ञानिक केंद्र है।

डीएनए फोरेंसिक्स, ड्रोन फोरेंसिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय अनुसंधान कर रही इस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत", 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के सतत मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) आज वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने में अग्रणी स्थान रखती है जो गुजरात और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

एनएफएसयू की विकास यात्रा के संदर्भ में विभिन्न महानुभावों एवं विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं

विश्वप्रसिद्ध कथाकार और आध्यात्मिक मार्गदर्शक पूज्य भाईश्री रमेशभाई ओझा ने एनएफएसयू की यात्रा के दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। जब भी कोई अपराधी कोई समस्या उत्पन्न करता है, तब एनएफएसयू जैसी विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी उसके समाधान के लिए कटिबद्ध है। मैं इस विश्वप्रसिद्ध नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का दौरा कर अत्यंत प्रसन्न हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देखा गया यह सपना कि भारत फोरेंसिक क्षेत्र में अग्रणी बने और अनेक देशों की फोरेंसिक क्षमता निर्माण में सहायता करे, उसे एनएफएसयू ने वास्तविक रूप में चरितार्थ किया है।

नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू), गांधीनगर द्वारा 'माय लाइफः माय स्टोरी' विषय पर इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ श्री रजत शर्मा के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

श्री रजत शर्मा ने कहा था कि सोशल मीडिया के इस दौर में 'फेक न्यूज' और 'डीप फेक' गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। ऐसे समय में इस प्रकार के भ्रामक वीडियो की समस्या का समाधान करने तथा समाज में जागरूकता फैलाने के कार्य में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की MBA छात्रा डॉ. निशा वाला ने कहा कि "NFSU में अध्ययन करना एक उत्कृष्ट वैश्विक अनुभव है। यहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर, करियर-केंद्रित मार्गदर्शन देने वाले अत्यंत ज्ञानवान प्रोफेसर तथा सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।" एमटेक स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स के छात्र श्री नाई वेद ने कहा "एनएफएसयू में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जिसका उपयोग हमारे शोध कार्य में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है।"

नई टीम के साथ समाज सेवा की नई दिशा, उधना-गोडादरा माहेश्वरी सभा की कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन

सूरत। सामाजिक एकता, संगठनात्मक मजबूती और समाज सेवा के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की दिशा में उधना-गोडादरा माहेश्वरी समाज ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है। सूरत जिला माहेश्वरी सभा के अंतर्गत आने वाली उधना-गोडादरा माहेश्वरी सभा की नई टीम का चयन शनिवार को सर्वसम्मति से किया गया। समाज के वरिष्ठजनों और सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई इस प्रक्रिया ने संगठन की लोकतांत्रिक परंपरा और सामाजिक समरसता को भी रेखांकित किया।

सभा परिवार के वरिष्ठ सदस्य दामोदर राठी ने नई कार्यकारिणी के गठन की जानकारी देते हुए बताया कि समाज के विकास, संगठनात्मक गतिविधियों के विस्तार तथा सामाजिक दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने कहा कि नई टीम के गठन से समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में नई ऊर्जा का संचार होगा।

सर्वसम्मति से हुए चयन के तहत समाज के सक्रिय और अनुभवी सदस्य सत्यनारायण देवपुरा को उधना-गोडादरा माहेश्वरी सभा का अध्यक्ष चुना गया है। वहीं संगठनात्मक कार्यों के संचालन

और विभिन्न गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी दिनेश चांडक को सचिव के रूप में सौंपी गई है। इसके अलावा महेश साबू और जगदीश कोठारी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि श्याम सुंदर राठी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

नई कार्यकारिणी में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से मुकेश न्याति को संगठन मंत्री बनाया गया है। वहीं सुनील न्याति और अमित राठी को सहसचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाज के सदस्यों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि माहेश्वरी समाज हमेशा से शिक्षा, सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। नई कार्यकारिणी से भी उम्मीद की जा रही है कि वह समाज की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठजनों को जोड़कर संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगी।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण देवपुरा ने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की एकता और विकास उनकी प्राथमिकता होगी तथा सभी सदस्यों के सहयोग से संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

सचिव दिनेश चांडक ने भी समाज के विश्वास के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि संगठनात्मक गतिविधियों को अधिक प्रभावी और सक्रिय बनाने के लिए नई योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक कार्यक्रमों को विस्तार देने तथा समाजहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।

बैठक में उपस्थित समाजजनों ने भी नई टीम से अपेक्षा जताई कि वह सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों और सेवा भाव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलेगी। कार्यक्रम के दौरान समाज के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया और भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक सुझाव सामने आए।

समारोह के अंत में सभी सदस्यों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर नई कार्यकारिणी को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। पूरे आयोजन में उत्साह और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। समाज के वरिष्ठजनों ने विश्वास व्यक्त किया कि नई टीम के नेतृत्व में उधना-गोडादरा माहेश्वरी सभा सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा गतिविधियों के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगी तथा समाज के हित में निरंतर कार्य करती रहेगी।

खाकी ने निभाया मां का फर्ज, लावारिस नवजात 'कशिश' की छठी मनाकर पुलिस ने दिया नया परिवार

सूरत। आमतौर पर पुलिस की पहचान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध पर अंकुश लगाने और सुरक्षा प्रदान करने वाली संस्था के रूप में की जाती है, लेकिन सूरत के पांडेसरा पुलिस स्टेशन ने मानवता, संवेदनशीलता और ममता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। एक लावारिस हालत में मिली नवजात बच्ची को न केवल जीवनदान मिला, बल्कि उसे वह प्यार और अपनापन भी मिला जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। पुलिसकर्मियों ने बच्ची की देखभाल करते हुए उसकी 'छठी' मनाई, नामकरण संस्कार कराया और उसे परिवार जैसा स्नेह देकर यह साबित कर दिया कि खाकी वर्दी के भीतर भी एक संवेदनशील दिल धड़कता है।

यह मार्मिक कहानी 21 मई 2026 से शुरू होती है। बमरोली रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच एक नवजात बच्ची चार पहिया वाहन के नीचे लावारिस अवस्था में पड़ी मिली। आसपास से गुजर रहे लोगों की नजर जब उस मासूम पर पड़ी तो सभी स्तब्ध रह गए। एक रिक्शा चालक ने मानवता का परिचय देते हुए तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना मिलते ही पांडेसरा पुलिस स्टेशन की पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए बच्ची को 108 एम्बुलेंस की सहायता से न्यू सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने पाया कि नवजात की हालत बेहद नाजुक थी। तेज गर्मी और लंबे समय तक खुले वातावरण में रहने के कारण उसके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा था। डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया, लेकिन इस दौरान जिस तरह पुलिसकर्मियों ने बच्ची की जिम्मेदारी उठाई, उसने इस घटना को एक अलग ही मानवीय आयाम दे दिया।

पांडेसरा पुलिस स्टेशन की महिला पुलिसकर्मियों ने बच्ची को केवल एक केस या जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे अपनी संतान की तरह अपनाया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने दिन-रात उसकी देखभाल की। कोई उसे गोद में लेकर सुलाता, कोई उसके लिए दूध और आवश्यक सामान की व्यवस्था करता, तो कोई उसकी सेहत की जानकारी लेने अस्पताल पहुंच जाता। लगातार 13 दिनों तक चले इस देखभाल अभियान में पुलिसकर्मियों ने ऐसा वात्सल्य दिखाया जिसने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों को भी भावुक कर दिया।

धीरे-धीरे बच्ची की सेहत में सुधार आने लगा। चिकित्सकों के उपचार और पुलिसकर्मियों की अथक सेवा के परिणामस्वरूप वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जब डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची अब खतरे से बाहर है, तब पांडेसरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसकी जिंदगी के इस नए अध्याय को यादगार बनाने का निर्णय लिया।

एच डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त जेड.आर. देसाई और पांडेसरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक के.डी. जडेजा के मार्गदर्शन में नवजात की 'छठी' मनाने की योजना बनाई गई। आमतौर पर परिवारों में नवजात के जन्म के छठे दिन होने वाला यह पारंपरिक संस्कार पहली बार किसी पुलिस स्टेशन में इतने भावनात्मक तरीके से आयोजित किया गया।

समारोह के लिए पुलिस स्टेशन को विशेष रूप से सजाया गया। फूलों, रंग-बिरंगी सजावट और पारंपरिक धार्मिक व्यवस्थाओं के बीच पूरा माहौल किसी पारिवारिक उत्सव जैसा दिखाई दे रहा था। पुलिसकर्मी, अधिकारी और स्थानीय लोग इस अनूठे आयोजन के साक्षी बने। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के साथ नवजात का नामकरण संस्कार संपन्न कराया गया।

इस अवसर पर बच्ची का नाम 'कशिश' रखा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 'कशिश' शब्द का अर्थ आकर्षण, अपनापन और ऐसा भाव है जो सीधे दिल को छू ले। वास्तव में यह नाम उस मासूम के जीवन की कहानी को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है, जिसने अपने जन्म के कुछ ही दिनों में अनगिनत लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया।

नामकरण समारोह के दौरान बच्ची को ढेर सारे उपहार भी दिए गए। पुलिसकर्मियों और समाज के विभिन्न लोगों ने उसके लिए कपड़े, कंबल, खिलौने, बेबी केयर किट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट कीं। यह दृश्य किसी परिवार में नवजात के स्वागत जैसा था, जहां हर व्यक्ति उस मासूम के उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा था। इस पूरे आयोजन में महिला हेड कांस्टेबल भाग्यश्री वाघेला, तेजलबा परमार, केशवीबेन चावड़ा तथा 'शी टीम' की अन्य सदस्याओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केवल बच्ची की देखभाल ही नहीं की, बल्कि उसके प्रति मातृत्व भाव भी प्रदर्शित किया।

पंचायती राज मंत्रालय 9 जून 2026 को गांधीनगर गुजरात में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर आउटरीच कार्यशाला आयोजित करेगा

यह कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें गुजरात भर की पात्र ग्राम पंचायतों और तालुका पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा

भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय 9 जून 2026 को गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कर रहा है । इस कार्यशाला में श्री विवेक भारद्वाज , सचिव , पंचायती राज मंत्रालय , भारत सरकार ; श्रीमती मुक्ता शेखर , संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ; श्री धनंजय द्विवेदी , प्रधान सचिव, पंचायत , ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास विभाग , गुजरात सरकार ; और डॉ. गौरव दहिया , अतिरिक्त विकास आयुक्त , गुजरात सरकार , राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (एचयूडीसीओ) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधियों तथा पंचायतों के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ भाग लेंगे ।

यह कार्यशाला हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी । गांधीनगर के आसपास की पात्र पंचायतें व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगी , जबकि इस दायरे से बाहर की पंचायतें अपने -अपने कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव प्रसारण में शामिल होंगी । इस पहल के माध्यम से , मंत्रालय का उद्देश्य गुजरात भर में ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत स्तर के नेताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करना और उन्हें आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम की परिकल्पना , उद्देश्य और परिचालन रूपरेखा से अवगत कराना है ।

कार्यशाला के कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव द्वारा आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के दृष्टिकोण पर

संबोधन , राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों , तकनीकी रोडमैप और अपेक्षित परिणामों पर विस्तृत प्रस्तुति , आत्मनिर्भर पंचायत पोर्टल का पूर्ण - पूर्ण लाइव प्रदर्शन और एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र शामिल है । नाबार्ड और हुडको के प्रतिनिधि भी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के प्रति अपनी संस्थागत प्रतिबद्धता को दोहराएंगे ।

आत्मनिर्भर पंचायत कार्य क्रम भारत सरकार की एक पहल है , जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य पंचायतों की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना है । एक पारदर्शी राष्ट्रीय चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से , पंचायतों को आय सृजन करने वाली परियोजनाओं और पहलों के लिए विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है , जो अप्रयुक्त संपत्तियों और स्थानीय स्तर पर मौजूद अवसरों का उत्पादक उपयोग कर सकें । चयनित विचारों को मंत्रालय द्वारा व्यवहार्य और ऋण योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए समर्पित तकनीकी सहायता प्राप्त होगी , जिसमें सार्वजनिक - निजी भागीदारी (पीपीपी) , कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड , बैंक वित्त और अन्य सरकारी योजनाओं के समन्वय से वित्तीय सहायता शामिल होगी । योजना के प्रत्येक चरण में ग्राम सभा की अनिवार्य भागीदारी के माध्यम से सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित किया जाता है । कम से कम 50 लाख रुपये के स्व- स्रोत राजस्व (ओएसआर) वाली ग्राम पंचायतें और कम से कम 1 करोड़ रुपये के ओएसआर वाली तालुका पंचायतें , जिनका कार्यकाल कम से कम तीन वर्ष शेष हो , इस चुनौती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हैं । पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण परियोजना विकास में संस्थागत विशेषज्ञता प्रदान करने और पात्र पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड और एचयूडीको के साथ साझेदारी की है ।

आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है । इसका उद्देश्य स्वायत्त , आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर पंचायतों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करना है , जिनमें से प्रत्येक यह प्रदर्शित करेगी कि आर्थिक स्वतंत्रता और सुशासन साथ - साथ चलते हैं । मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुसार , आत्मनिर्भर पंचायतें आत्मनिर्भर भारत की सबसे मजबूत नींव हैं । गांधीनगर कार्यशाला गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम के विस्तार की शुरुआत का प्रतीक है ।

मुंबई लोकल की महिला कोच में युवकों ने महिलाओं को परेशान किया, महिलाओं की शिकायत के बावजूद आरपीएफ-जीआरपी ने कोई कार्रवाई नहीं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। जब देशभर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में शनिवार को मुंबई की एक लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे में एक युवक द्वारा की गई बदसलूकी की घटना से पता चलता है कि रेलवे पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितनी निष्क्रिय रही है। जब महिलाओं ने महिला डिब्बे में सवार युवक का विरोध किया और उसे डिब्बे से उतरने को कहा, तो युवक चौंक गया और उसने मना कर दिया और महिला यात्रियों से अभद्र भाषा में बात की।

एक युवक का महिलाओं से बहस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में महिलाएं उसे कोच से उतरने के लिए कहती सुनाई दे रही हैं। वीडियो में महिलाएं पहले युवक से लेडीज़ कोच से उतरने के लिए कहती हैं क्योंकि वह उसमें चढ़ चुका है। हालांकि, युवक इससे नाराज होकर कहता है कि महिलाएं जो चाहें करें, मैं नहीं उतरूंगा और खार स्टेशन पर उतर जाऊंगा। महिलाओं ने युवक को बताया कि ट्रेन खार स्टेशन से आगे निकल चुकी है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जा रही है, लेकिन युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। अंततः, बांद्रा स्टेशन पर महिलाओं के डिब्बे में चढ़ने के बाद भी युवक ने किसी की बात नहीं सुनी और किंग्स सर्कल स्टेशन पर एक महिला को धक्का देकर भाग गया।

अगर आप 1512 हेल्पलाइन पर भरोसा करेंगे तो यह काम नहीं करेगा।

महिलाओं के डिब्बे में चढ़े उस "चक्कर आने" से परेशान युवक ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद नीचे नहीं उतरा, इसलिए महिलाओं ने रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) की हेल्पलाइन 1512 पर फोन किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अगर महिलाओं के डिब्बे में सिर्फ दो या तीन महिलाएं ही सफर कर रही होतीं, तो सोचिए वह युवक क्या करता? इस घटना से लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है।

अध्ययन से पता चला : सस्ती जेनेरिक दवाएं महंगी ब्रांडेड दवाओं जितनी ही प्रभावी हैं, 100% नमूने परीक्षण में पास हुए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। केरल स्थित शोध संस्थान "फंड्स इन फार्माकोलॉजी" द्वारा डॉ. एबी फिलिप्स के नेतृत्व में और सात अन्य डॉक्टरों की एक टीम द्वारा एक अध्ययन किया गया। डॉ. फिलिप्स केरल के कोच्चि स्थित राजगिरी अस्पताल से जुड़े हैं और सोशल मीडिया पर "लिवर डॉक्टर" के नाम से मशहूर हैं। क्या सस्ती जेनेरिक दवाएं वाकई महंगी ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार होती हैं?

यह एक ऐसा सवाल है जिसने न केवल मरीजों को बल्कि कई डॉक्टरों को भी लंबे समय से परेशान किया है। आम धारणा यह है कि कम कीमत कम गुणवत्ता का संकेत देती है। भारत जैसे देश में यह संदेह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च का लगभग दो-तिहाई हिस्सा दवाओं पर खर्च होता है।

डॉ. फिलिप्स के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में केरल के विभिन्न क्षेत्रों से आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 22 दवाओं के 131 नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों में हृदय रोग, मधुमेह, संक्रमण, दर्द, एसिडिटी और अन्य बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल थीं। ये नमूने सात अलग-अलग प्रकार के खुदरा दुकानों से एकत्र किए गए थे। इनमें सरकारी जन औषधि केंद्र (जेनेरिक दवा केंद्र) और जेनेरिक व महंगी ब्रांडेड दवाएं बेचने वाली फार्मेसियां शामिल थीं।

इस अध्ययन का वित्तपोषण सार्वजनिक योगदान से किया गया था। सभी नमूनों को कोडिंग और रैंडमाइजेशन प्रणाली के तहत एक उच्च स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां भारतीय फार्माकोपिया 2022 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उनका कड़ाई से परीक्षण किया गया। इस अध्ययन की एक अनूठी विशेषता यह थी कि इससे पहले बहुत कम शोध प्रयासों में बाजार से खरीदी गई ब्रांडेड और जेनेरिक दवाओं की सीधे तुलना की गई है, जिनमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाएं भी शामिल हैं, या गुणवत्ता परीक्षण के साथ-साथ कीमत का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

दूसरे शब्दों में कहें तो, सफलता दर 100% थी। दवा चाहे जेनेरिक हो या ब्रांडेड, सस्ती हो या महंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी मामलों में, सक्रिय औषधीय घटक की मात्रा, शुद्धता और घुलनशीलता दर निर्धारित मानकों के पूर्ण अनुपालन में पाई गई।

मिडिल ईस्ट संकट ने उड़ान उद्योग की बढ़ाई चिंता, मुनाफे पर गहराया दबाव

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष का असर अब केवल तेल बाजारों या वैश्विक व्यापार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के बावजूद एयरलाइंस कंपनियां बढ़ती लागत, ईंधन कीमतों में उछाल और हवाई मार्गों में आ रही बाधाओं के कारण गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक विमानन उद्योग के लाभ अनुमान में उल्लेखनीय कटौती करते हुए उद्योग के सामने खड़ी नई चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वैश्विक स्तर पर एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था IATA की ताजा रिपोर्ट बताती है कि मिडिल ईस्ट संकट ने विमानन क्षेत्र की आर्थिक गणनाओं को पूरी तरह बदल दिया है। संस्था के अनुसार, पहले जहां वर्ष 2026 में वैश्विक एयरलाइन उद्योग के संयुक्त शुद्ध लाभ का अनुमान लगभग 41 अरब डॉलर लगाया गया था, वहीं अब इसे घटाकर लगभग 23 अरब डॉलर कर दिया गया है। यह कटौती दर्शाती है कि उद्योग की वित्तीय स्थिति पर युद्ध और अस्थिरता का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तुलना करें तो वर्ष 2025 में एयरलाइन उद्योग का अनुमानित लाभ 45 अरब डॉलर के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि विमानन उद्योग की सबसे बड़ी चुनौती ईंधन लागत में तेज वृद्धि है। किसी भी एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च में ईंधन का हिस्सा पहले से ही काफी बड़ा होता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह बोझ और बढ़ गया है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण कच्चे तेल और जेट फ्यूल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। एयरलाइंस को आशंका है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईंधन लागत और अधिक बढ़ सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। IATA के महानिदेशक विली वॉल्श ने कहा है कि मुनाफे के अनुमान में कमी के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, जेट फ्यूल की कीमतों में अपेक्षा से अधिक वृद्धि और दूसरा, खाड़ी क्षेत्र से जुड़े हवाई मार्गों में उत्पन्न परिचालन संबंधी कठिनाइयां। युद्ध और सुरक्षा चिंताओं के चलते कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं या उड़ानों के लिए विशेष सावधानियां लागू की हैं। इसके परिणामस्वरूप एयरलाइंस को वैकल्पिक और लंबे मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। लंबे मार्गों का सीधा असर परिचालन लागत पर पड़ता है। जब विमान को गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है तो ईंधन की खपत बढ़ जाती है। इसके अलावा चालक दल के कार्य घंटे, विमान रखरखाव और समय प्रबंधन जैसी चुनौतियां भी बढ़ती हैं। कई एयरलाइंस को अपने उड़ान कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ा है, जिससे यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइंस का कुल ईंधन व्यय वर्ष 2025 के लगभग 252 अरब डॉलर से बढ़कर 2026 में 350 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि विमानन उद्योग के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ईंधन खर्च अब कुल परिचालन लागत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बन सकता है। ऐसी स्थिति में एयरलाइंस के लिए लाभ बनाए रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो जाएगा। इस संकट का असर यात्रियों की जेब पर भी पड़ने की संभावना है। एयरलाइंस जब बढ़ी हुई लागत का सामना करती हैं तो उसका एक हिस्सा टिकट कीमतों के रूप में ग्राहकों पर स्थानांतरित किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के किराए पहले से ही ऊंचे बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में हवाई किरायों में बड़ी कमी की संभावना नहीं है, क्योंकि एक ओर लागत बढ़ रही है और दूसरी ओर यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है। दुनिया भर में पर्यटन, व्यापारिक यात्राओं और पारिवारिक यात्राओं की मांग लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी के बाद यात्रा क्षेत्र में आई तेजी ने एयरलाइंस को राहत दी थी, लेकिन अब नई भू-राजनीतिक चुनौतियां उस सुधार की गति को प्रभावित कर रही हैं।

गुजरात के युवाओं को एआई से लेकर ईवी जैसे अत्याधुनिक पाठ्यक्रमों का मिलेगा प्रशिक्षण: राज्य के आईटीआई में शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम

▸▸ राज्यभर के आईटीआई में एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग, सोलर एनर्जी और 3डी प्रिंटिंग जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में उभरते क्षेत्रों के लिए कुशल मानवबल तैयार करने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

गांधीनगर : तकनीकी शिक्षा को उभरते औद्योगिक रुझानों के अनुरूप बनाने के लिए गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में कई 'न्यू एज' पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

नए पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्रोन पायलट, सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल), सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीशियन (3डी प्रिंटिंग), तकनीशियन मेकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग (सीएएम) प्रोग्रामर, आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट एग्रीकल्चर), आईओटी तकनीशियन (स्मार्ट सिटी) और स्मार्टफोन तकनीशियन-सह-ऐप टेस्टर जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं।

गुजरात के श्रम, कौशल विकास और रोजगार मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावलिया ने कहा, "ये पाठ्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑटोमेशन, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए कुशल मानवबल तैयार करने के लिए शुरू किए गए हैं।"

वहीं, श्रम, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री श्री कांतिलाल अमृतिया ने कहा, "राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में इन न्यू-एज पाठ्यक्रमों को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण प्रणाली को बदलती औद्योगिक जरूरतों के सुसंगत बनाए रखना है। इन पाठ्यक्रमों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।"

गुजरात के सरकारी, अनुदानित और स्ववित्तपोषित आईटीआई में कुल 11 नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, इस संदर्भ में प्रशिक्षुओं के लिए 3312 नई सीटें जोड़ी गई हैं। इसके अंतर्गत, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर तकनीशियन (इलेक्ट्रिकल) पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किए गए है, जबकि अन्य विशिष्ट पाठ्यक्रम चुनिंदा आईटीआई में शुरू किए गए हैं।

टेक्नोलॉजी-आधारित ये नए पाठ्यक्रम राज्य के कुल 73 आईटीआई में शुरू किए गए हैं, जिनमें से 67 सरकारी आईटीआई, 2 अनुदानित संस्थान और 4 स्ववित्तपोषित संस्थान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं का कौशल बढ़ाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है, साथ ही बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। गुजरात सरकार उनके इस विजन का अनुसरण करते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में नए विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए कुशल मानवबल तैयार करने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

एक अधिकारी ने कहा, "गुजरात देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 16.5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ भारत के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। दिसंबर 2025 तक राज्य की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 42.583 गीगावाट तक पहुंच गई थी।"

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गुजरात कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देशभर में अव्वल है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता में दूसरे स्थान पर है।

अधिकारी ने आगे कहा, "सौर ऊर्जा क्षेत्र में विशाल रोजगार की संभावनाएं हैं और आईटीआई में सोलर तकनीशियन का पाठ्यक्रम शुरू होने से उद्योग के लिए कुशल मानवबल तैयार होगा।"

इसी प्रकार, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बढ़ते इस्तेमाल के कारण प्रशिक्षित ईवी तकनीशियन की मांग भी बढ़ेगी। इस वर्ष (2026) की शुरुआत में गुजरात के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। मार्च 2026 के दौरान राज्य में ईवी रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 75.5 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़ती उपभोक्ता मांग, सरकारी प्रोत्साहनों और कर राहत जैसे कदमों के कारण संभव हुई।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 में गुजरात में 12,729 ईवी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जबकि गत वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 7252 यूनिट था। वहीं, केवल शुद्ध इलेक्ट्रिक (यानी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), जो पूरी तरह से बिजली पर चलने वाले होते हैं) वाहनों का रजिस्ट्रेशन 111 फीसदी की वृद्धि के साथ 5271 यूनिट से बढ़कर 11,126 यूनिट तक पहुंच गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की मांग भी बढ़ेगी। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए ईवी मेकेनिक से संबंधित पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।"

राज्यभर के विभिन्न आईटीआई में प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए 40 इलेक्ट्रिक वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

अभी गुजरात में 288 सरकारी आईटीआई हैं, जिनमें 1,77,912 सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 100 अनुदानित आईटीआई में 16,200 सीटें और 171 स्ववित्तपोषित आईटीआई में 24,624 सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रकार, राज्य में कुल 560 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) हैं, जिनमें कुल मिलाकर 2,18,736 सीटें उपलब्ध है।

वर्तमान में गुजरात के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 138 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

बावला स्टेशन यार्ड स्थित एलएचएस-62ए सार्वजनिक आवागमन हेतु अस्थायी रूप से बंद

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल ने जनसामान्य को सूचित किया है कि साबरमती–बोटाद रेलखंड के किमी 46/7-8 पर स्थित बावला स्टेशन यार्ड के एलएचएस क्रमांक 62ए (LHS-62A) को नगरपालिका बावला द्वारा किए जा रहे नाले (ड्रेन) निर्माण कार्य के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सभी प्रकार के सार्वजनिक आवागमन एवं वाहन परिचालन के लिए पूर्णतः बंद रखा जाएगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निर्माण कार्य को सुरक्षित, सुचारु एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निर्माण अवधि के दौरान उक्त मार्ग से किसी भी प्रकार के दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहन अथवा पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा कार्यस्थल पर प्रदर्शित यातायात एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं आवश्यक सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात मार्ग को पुनः खोलने की सूचना पृथक से जारी की जाएगी।

रेल प्रशासन द्वारा जनसामान्य से अनुरोध किया जाता है कि वे बंदी अवधि के दौरान उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार का आवागमन न करें तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

भावनगर मंडल, पश्चिम रेलवे इस अस्थायी व्यवस्था से होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है तथा नागरिकों के सहयोग एवं समझदारी के लिए आभार प्रकट करता है।

जनसेवा को समर्पित जीवन को अंतिम नमन, योगेशभाई पटेल की प्रार्थना सभा में उमड़ा जनसैलाब

वडोदरा। मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्षों तक जनसेवा और विकास कार्यों को नई दिशा देने वाले वरिष्ठ विधायक योगेशभाई पटेल को रविवार को वडोदरा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नवलखी ग्राउंड में आयोजित उनकी प्रार्थना सभा में राजनीतिक, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े हजारों लोगों की उपस्थिति ने यह प्रमाणित कर दिया कि योगेशभाई पटेल केवल एक जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि जनता के बीच गहरी पैठ रखने वाले लोकप्रिय नेता थे। सभा में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने दिवंगत नेता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके परिवारजनों को सांत्वना दी। प्रार्थना सभा का वातावरण भावुकता और श्रद्धा से भरा हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिवंगत योगेशभाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि योगेशभाई पटेल का निधन केवल उनके परिवार या निर्वाचन क्षेत्र की

ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात की अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने उनके सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के प्रति समर्पण को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सदैव जनता के हितों को प्राथमिकता दी और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

योगेशभाई पटेल लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र के विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक मुद्दों पर प्रभावी कार्य किया। यही कारण रहा कि उनके निधन की खबर के बाद विभिन्न वर्गों में शोक की लहर फैल गई थी। प्रार्थना सभा में उमड़ी भीड़ ने भी उनके प्रति लोगों के स्नेह और सम्मान को स्पष्ट रूप से दर्शाया। सभा में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री भी उपस्थित रहे। मंत्री रमनभाई सोलंकी, मंत्री मनीषाबेन वकील, दंडक बालकृष्णभाई शुक्ला, विधायक केतन ईनामदार, पूर्व मंत्री एवं विधायक जयद्रथ सिंह परमार, पूर्व गृह मंत्री गोरधनभाई झडफिया तथा पूर्व मंत्री राजेन्द्र त्रिवेदी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी इस बात का संकेत थी कि योगेशभाई पटेल ने राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सभी वर्गों के बीच सम्मान अर्जित किया था।

प्रार्थना सभा में सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी भाग लिया। उपस्थित लोगों ने दिवंगत नेता के साथ जुड़े अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा कि योगेशभाई पटेल हमेशा लोगों के सुख-दुख में सहभागी बनने वाले नेता थे। आम नागरिकों के बीच उनकी सहज उपलब्धता और समस्याओं के समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। सभा के दौरान कई वक्ताओं ने उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि योगेशभाई पटेल ने अपने सार्वजनिक जीवन में विकास और जनकल्याण को केंद्र में रखा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और नागरिक सुविधाओं से जुड़े अनेक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उनके प्रयासों से मांजलपुर क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं को गति मिली और स्थानीय स्तर पर लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकीं। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण गंभीर और भावुक बना रहा। कई लोगों की आंखें नम दिखाई दीं, जो योगेशभाई पटेल के प्रति उनके सम्मान और आत्मीय संबंधों को दर्शा रही थीं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगेशभाई पटेल का व्यक्तित्व उन नेताओं में शामिल था जिन्होंने संगठन और जनप्रतिनिधित्व दोनों स्तरों पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि समाज सेवा का दायित्व माना। यही कारण है कि उनके निधन के बाद विभिन्न क्षेत्रों से लगातार श्रद्धांजलि संदेश सामने आ रहे हैं। वडोदरा में आयोजित यह प्रार्थना सभा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि यह उस जननेता के प्रति सामूहिक सम्मान का प्रतीक बन गई जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जनता की सेवा में समर्पित किया। श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे लोगों ने कहा कि योगेशभाई पटेल भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य, उनकी सादगी और जनसेवा की भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने धोला-जेतपुर-जेतलसर-उपलेटा-भायावदर-वांसजालिया सेक्शन का किया विंडो ट्रेलिंग एवं संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री दिनेश वर्मा ने दिनांक 06 जून, 2026 (शनिवार) को धोला जंक्शन स्टेशन से वांसजालिया जंक्शन स्टेशन तक विस्तृत विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धोला जंक्शन, जेतपुर, जेतलसर, उपलेटा, भायावदर एवं वांसजालिया स्टेशनों का संरक्षा, परिचालन एवं यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से गहन निरीक्षण किया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान श्री वर्मा ने धोला-जेतपुर-जेतलसर-उपलेटा-भायावदर-वांसजालिया खंड में प्रगति पर चल रहे कार्यों का विशेष रूप से जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन तथा कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त, मंडल रेल प्रबंधक ने सेक्शन में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों, पथ संरचना, सिग्नल एवं दूरसंचार व्यवस्थाओं तथा अन्य रेल अधोसंरचना संबंधी व्यवस्थाओं का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने रेल परिसंपत्तियों के रखरखाव एवं संरक्षा मानकों के प्रति विशेष सतर्कता बरतने पर बल दिया।

श्री वर्मा ने यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं जैसे स्टेशन परिसर की स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सुविधाएं तथा यात्री सुरक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि रेल संचालन में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा संरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक कर्मचारी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उच्च स्तर की सतर्कता, समन्वय और कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

इस निरीक्षण के दौरान मंडल के विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस (ILCAD-2026) के अंतर्गत विशेष जनजागरण अभियान

रेलवे संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD-2026) के अवसर पर दिनांक 07 जून से 09 जून 2026 तक व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष अभियान का मुख्य संदेश "सुरक्षा प्रथम, हमेशा और हर जगह" (Safety First, Always and Everywhere) है।

मंडल के वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी (Sr. DSO) श्री मानिक गुप्ता के निर्देशन में सभी यातायात निरीक्षक (TI), सेक्शन कंट्रोलर (SC), वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (पथ) [SSE(P. Way)], स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर (SS) तथा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र के प्रमुख समपार फाटकों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के दौरान रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी आमजन, वाहन चालकों, स्कूली विद्यार्थियों तथा स्थानीय नागरिकों को समपार फाटकों पर सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करेंगे। उन्हें बंद फाटक को पार न करने, फाटक खुलने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने, रेलगाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा न करने तथा रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जनजागरूकता कार्यक्रमों में पंपलेट वितरण, सुरक्षा शपथ, जनसंवाद, उद्घोषणाएं तथा सुरक्षा संदेशों का प्रसार किया जाएगा। साथ ही रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 160 के अंतर्गत समपार फाटक से संबंधित नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होने तथा दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक के कारावास के प्रावधान की भी जानकारी दी जाएगी।

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने आमजन से अपील किया है कि समपार फाटकों पर सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित रेल संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें। जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

सिंगनपोर की रात बनी खौफनाक, मामूली कहासुनी ने छीन ली दो जिंदगियां

सूरत। शहर के सिंगनपोर क्षेत्र में शनिवार देर रात हुई एक हिंसक वारदात ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि छोटी-छोटी बातों पर बढ़ती आक्रामकता किस तरह युवाओं की जान ले रही है। मावा खाने और बंद दुकान खुलवाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते इतना गंभीर हो गया कि दो दोस्तों की जान चली गई। डबल मर्डर की इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

पुलिस के अनुसार, लिंबायत के संजयनगर निवासी 30 वर्षीय हर्षल अधिकारीभाई पाटिल और वेड रोड स्थित बापासीताराम चौक निवासी 25 वर्षीय भटू वनराजभाई माली शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि अपने कुछ मित्रों के साथ डभोली गांव के पास बजरंगनगर इलाके में पहुंचे थे। बताया जाता है कि समूह मावा खाने के लिए वहां आया था। देर रात होने के कारण अधिकांश दुकानें बंद थीं। इसी दौरान एक बंद पान की दुकान खुलवाने को लेकर वहां मौजूद लोगों और युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुरू में मामला केवल बहस तक सीमित था, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि झगड़े के दौरान हर्षल और भटू कथित रूप से चाकू लेकर वापस आए थे। वहीं पान की दुकान के भीतर कैरम खेल रहे चार युवक भी विवाद में शामिल हो गए। इसके बाद स्थिति और अधिक हिंसक हो गई। आरोप है कि झड़प के दौरान आरोपियों ने दोनों युवकों से चाकू छीन लिए और उन्हीं हथियारों से उन पर हमला कर दिया।

हमलावरों ने हर्षल पाटिल की पीठ पर और भटू माली के पेट पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल दोनों युवक घटनास्थल पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़े। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को तत्काल स्मीमेर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए। हालांकि हर्षल पाटिल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भटू माली ने रविवार सुबह अंतिम सांस ली। इस प्रकार कुछ घंटों के अंतराल में दो परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए।

दोनों युवकों की मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों तक पहुंची, अस्पताल परिसर में मातम छा गया। परिजनों और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। अस्पताल में मौजूद लोगों की आंखें भी इस दर्दनाक दृश्य को देखकर नम हो गईं।

हर्षल पाटिल अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। परिवार के अनुसार वह अपने पिता के साथ ड्राइविंग और पार्सल परिवहन का कार्य करता था तथा परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। माता-पिता के लिए यह विश्वास करना भी मुश्किल हो रहा है कि उनका इकलौता बेटा अब उनके बीच नहीं रहा।

वहीं भटू वनराजभाई माली अपने परिवार का सबसे छोटा पुत्र था। परिवार में उसके बड़े भाई और दो बहनें हैं। घर के सबसे छोटे सदस्य होने के कारण वह सभी का लाड़ला था। उसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। परिजनों का कहना है कि कुछ घंटे पहले तक जो युवक हंसते-बोलते घर से निकला था, वह अब कभी वापस नहीं आएगा।

घटना के बाद सिंगनपोर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज अपने कब्जे में ले लिए। फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई।

डीसीपी आलोक कुमार ने बताया कि मामले में शामिल चार आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल कवचड़ और पिंकस वालेकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि झड़प के दौरान पिंकस वालेकर भी घायल हुआ था और उसका उपचार पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस ने मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों तेजस कल्लू और अक्षय मोरे को वांछित घोषित किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सिंगनपोर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ा दिया है। जांच अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि घटना केवल तत्काल हुए विवाद का परिणाम थी या इसके पीछे किसी प्रकार की पुरानी रंजिश भी मौजूद थी। पुलिस दोनों पक्षों के आपराधिक और सामाजिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक दोनों युवकों के खिलाफ पहले भी मारपीट सहित कुछ आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वर्तमान मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

इस दोहरे हत्याकांड ने सिंगनपोर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था तथा युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली विवादों का इस तरह जानलेवा रूप लेना समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। वहीं पुलिस का मानना है कि यदि समय रहते झगड़े को शांत कर लिया जाता तो शायद दो युवाओं की जान बचाई जा सकती थी।

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। शहर में चर्चित बन चुके इस डबल मर्डर केस पर अब सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि जांच के आगे बढ़ने के साथ कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है।

निजी निवेश की नई उड़ान से बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर, उद्योग जगत ने दिखाया अभूतपूर्व भरोसा

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लंबे समय से जिस निजी निवेश चक्र के मजबूत होने का इंतजार किया जा रहा था, उसके स्पष्ट संकेत अब दिखाई देने लगे हैं। देश में औद्योगिक गतिविधियों, उत्पादन क्षमता विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कॉरपोरेट जगत का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र की निवेश घोषणाओं ने नया रिकॉर्ड बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग 56 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष के 37 लाख करोड़ रुपये की तुलना में बेहद उल्लेखनीय वृद्धि मानी जा रही है।

यह आंकड़ा केवल निवेश की बढ़ती संभावनाओं का संकेत नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारतीय उद्योग जगत भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि घोषित निवेश योजनाओं का बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरता है तो इससे देश की आर्थिक विकास दर, रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात क्षमता को नई गति मिल सकती है। एसबीआई रिसर्च की इकोव्रैप रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेश घोषणाओं में लगातार वृद्धि यह दर्शाती है कि कंपनियां अब केवल मौजूदा मांग को पूरा करने पर ही ध्यान नहीं दे रहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपनी उत्पादन क्षमता का भी विस्तार कर रही हैं। उद्योग जगत का यह बढ़ता आत्मविश्वास ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है और दुनिया के अनेक देशों में निवेश गतिविधियां अपेक्षाकृत धीमी पड़ी हुई हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में निवेश का परिदृश्य पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। वित्त वर्ष 2018-19 में जहां कुल निवेश घोषणाओं का आकार लगभग 17 लाख करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर करीब 80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि केवल आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना और उद्योगों के बढ़ते विस्तार का संकेत भी है।

विश्लेषकों का कहना है कि निवेश घोषणाओं में इस तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर लगातार बढ़ाया जा रहा खर्च, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली नीतियां, लॉजिस्टिक्स में सुधार तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार उद्योगों को नए निवेश के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके साथ ही भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिशों ने भी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। निवेश के क्षेत्रवार विश्लेषण पर नजर डालें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे आगे दिखाई देता है। कुल निवेश घोषणाओं में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 28.9 प्रतिशत रही है। यह संकेत देता है कि भारत में विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार को लेकर कंपनियां बड़े स्तर पर निवेश की योजना बना रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह निवेश वास्तविक परियोजनाओं में बदलता है तो देश की उत्पादन क्षमता में बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है।

मैन्युफैक्चरिंग के बाद पावर सेक्टर दूसरा सबसे बड़ा निवेश आकर्षित करने वाला क्षेत्र बनकर उभरा है। कुल निवेश प्रस्तावों में इसकी हिस्सेदारी लगभग 28.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निवेश को भारत की बढ़ती बिजली मांग, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार और औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और बिजली वितरण नेटवर्क में बड़े निवेश की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी निवेशकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। कुल निवेश घोषणाओं में इसकी हिस्सेदारी 23.1 प्रतिशत रही है। सड़क, रेल, मेट्रो, बंदरगाह, औद्योगिक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी और शहरी विकास परियोजनाओं में लगातार बढ़ते निवेश से इस क्षेत्र को मजबूती मिल रही है। माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचे में होने वाला यह निवेश देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि का मजबूत आधार तैयार करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल निवेश घोषणाएं ही नहीं, बल्कि वास्तविक आर्थिक आंकड़े भी इस सकारात्मक रुझान की पुष्टि करते हैं। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation-GFCF) में आई तेजी इसका प्रमुख उदाहरण है।